>

Title: Regarding reported killings of Buddhist monks in Lhasa, Tibet.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : सभापति जी, पिछले एक सप्ताह से तिब्बत में नरसंहार हो रहा है। अब तक की सूचना के मुताबिक, चीन सरकार द्वारा तिब्बत में वहां के सौ से ज्यादा निवासियों की हत्या कर दी गई है। यह केवल नरसंहार ही नहीं है बल्कि सांस्कृतिक नरसंहार हो रहा है। चीन सरकार की यह परिपाटी रही है कि वह अपने यहां रक्त रंजित तरीके से विपक्ष या विरोधियों को समाप्त करते हैं। पहले तियानेनमेन स्कवायर में इसी तरह से उन पर टैंक्स चढ़ा दिए गए थे और हजारों आदमी मार दिए गए थे। पिछले पचास सालों से लगातार सांस्कृतिक तौर पर तिब्बत को समाप्त करने, तिब्बत की संस्कृति को समाप्त करने, तिब्बत में रहने वाले, विशेष तौर पर बौद्ध धर्मावलम्बियों को समाप्त करने का षडयंत्र रचा जा रहा है।, इस समय वहां शान्तिपूर्वक प्रदर्शन हो रहे थे। चीन से लाकर लोगों को बसाकर तिब्बत की अपनी संस्कृति को नष्ट करने का जो प्रयास था, जब लोगों ने इसके विरोध में आवाज़ उठाई, तो उस आवाज़ को कुचलने के लिए वहां नरसंहार किया गया और सौ से ज्यादा लोग मार डाले गए। इस बारे में भारत सरकार को जोरदार वक्तव्य नहीं आया।[N17]

[MSOffice18] दुनिया भर की सरकारों ने इसकी निंदा की है। परन्तु भारत सरकार की ओर से अभी तक इस घटना की कोई निंदा नहीं की गयी। भारत सरकार की विशेष जिम्मेदारी है कि तिब्बत न केवल हमारा पड़ोसी देश है, बल्कि उससे हमारे सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं। धर्मगुरू दलाईलामा जी ने कहा है कि वे चीन से अलग होना नहीं चाहते, लेकिन उसकी स्वायत्तता, सांस्कृतिक स्वायत्तता को नष्ट होते हुए भी नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि सारा सदन तिब्बत में चीन द्वारा किये गये नरसंहार की निंदा करे। भारत सरकार इस बारे में अपना व्यक्तव दे और चीन से आग्रह किया जाये कि वे इस नरसंहार को तुंत बंद करे।

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। चीन ने तिब्बत में जन युद्ध की घोषणा कर दी है। तिब्बत की राजधानी में जो खून-खराबा हुआ है, उस बारे में चीनी सरकार क्या कहती है, वह अलग बात है। लेकिन धर्मगुरू दलाई लामा का जो बयान अखबारों में छपा है, उसके मुताबिक कम से कम वहां 100 बौद्ध भिक्षु मारे गये हैं। तिब्बत एक लंबे समय तक आजाद रहा है। वर्ष 1950 में जब चीन ने वहां फौजें भेजी तभी डा. लोहिया ने कहा था कि यह शिशु हत्या है। वर्ष 1959 से धर्मगुरू दलाई लामा हमारे यहां शरण लिये हुए हैं। पंडित नेहरू जी ने कहा था कि ये हमारे अतिथि हैं।

सभापति महोदय, वहां जो कुछ हो रहा है, वह अत्यधिक गंभीर है। तिब्बत के लोगों में जागृति आयी है। वे दुनिया के तमाम हिस्सों में रहकर अपनी आजादी के आंदोलन को इस तरह से सक्रिय कर रहे हैं। जहां तक स्वायत्तता का सवाल है, उस बारे में दलाई लामा का बयान अखबारों में छपा हैं। वहां आर्थिक विकास और किसी भी सवाल पर लोगों से संपर्क नहीं किया जाता। स्वायत्तता के नाम पर कोई भी जानकारी हासिल नहीं कर पाता। 10 मार्च को उनकी आजादी की लड़ाई का 49वां वर्ष था। उसके बाद से ये लोग बराबर अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं।

महोदय, न सिर्फ तिब्बत की राजधानी ल्हासा में, बल्कि दुनिया के हर कोने में, संयुक्त राष्ट्र में भी लोगों ने इस सवाल पर प्रदर्शन किये हैं। लोग अपने विरोध का इजहार कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन आदि ऐसे देश हैं, जिन्होंने अपना एतराज जताया है कि चीन जिस तरह से मानवाधिकारों को रौंद रहा है, वे किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। जार्ज बुश ने भी कहा है कि चीनी सरकार दलाई लामा से बात करे और दमन का रास्ता बंद करे। संयुक्त राष्ट्र ने चीन को चेताया है कि अगर उसने तिब्बत में व्यवस्था बनाने के नाम पर आजादी समर्थकों को कुचलना बंद नहीं किया, तो उसके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

महोदय, मैं आपकी मार्फत एक ही निवेदन करूंगा जिसे मैंने समाचार पत्रों में देखा है। जहां एक तरफ यह घटना हो रही है वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट सचिव का मंत्रियों को एक फरमान जारी हुआ है कि वह दलाई लामा के स्वागत समारोह में नहीं जायेंगे। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी बात पूरी हो गयी है।

â€¦(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। ...(व्यवधान) एक तरफ कैबिनेट सचिव का यह फरमान जारी होता है कि मंत्री लोग दलाई लामा के स्वागत समारोह में नहीं जायेंगे वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने कहा है कि चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन के समय कानून व्यवस्था का पालन करें और ऐसे राजनीतिक क्रिया-कलापों से बचें जिससे मित्र देशों से रिश्ते प्रभावित न हों।

महोदय, यह किसी भी कीमत पर न्याय संगत नहीं है। हम जरूर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से दुनिया के तमाम देश चिंतित हैं उसी तरह भारत का उसमें क्या रूख है? भारत अपने दृष्टिकोण से इस संसद को अवगत कराये।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, पिछले एक सप्ताह से चीन द्वारा तिब्बत में जो कुछ किया जा रहा है, वह अत्यंत शर्मनाक है। वह न केवल मानवाधिकारों का बल्कि मानवता का एक प्रकार से नरसंहार ही कहा जायेगा। चीन आज से नहीं, बहुत पहले से अपनी विस्तारवादी नीति के तहत कार्य कर रहा है। चीन की उस विस्तारवादी नीति को हम लोग स्वयं देखते हैं जब भारत के माननीय प्रधान मंत्री अरुणाचल प्रदेश की यात्रा में गये थे। उस समय जिस प्रकार के वक्तव्य चीन सरकार द्वारा दिये गये थे, वे अत्यंत आपत्तिजनक थे। भारत सरकार को तिब्बत के मामले में पुरजोर विरोध करना चाहिए, क्योंकि आज चीन के द्वारा जो कुछ तिब्बत में किया जा रहा है, उस देखते हुए हम चीन को फिर नेपाल में आने से रोक नहीं पायेंगे। जैसा आज न्यूज में आया भी है कि चीन की सेनाएं, चीन के अधिकारी नेपाल में घुसे हैं और कल नेपाल भी उसी प्रकार से चीन की विस्तारवादी नीति का शिकार होगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्य और तमाम क्षेत्र उसके शिकार होंगे। भारत सरकार को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि जो लोग चीन के नाम पर इस देश में राजनीति करने आए हैं, आज तिब्बत के मामले में भारत में उनकी चुप्पी आश्चर्यजनक हा ये लोग छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर राजनीति करते हैं। तिब्बत के अंदर इतना बड़ा नरसंहार किया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है।[MSOffice19]

ल्हासा में कहा जा रहा है कि अगर लोगों ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उनको घरों से निकालकर तोपों और बख्तरबंद वाहनों के नीचे कुचल दिया जाएगा। इस तरह की चेतावनियां वहां दी जा रही हैं। यह बहुत शर्मनाक स्थिति है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि चीन के जो प्रतिनिधि इस देश के अंदर बैठकर बार-बार इस देश की नीतियों को कोसते हैं, लेकिन आज चीन की इस प्रकार की शर्मनाक कार्यवाही और नरसंहार पर मौन बने हुए हैं, उन्हें भी अपने चेहरे को देश की जनता के सामने साफ करना चाहिए। चीन की इस कार्यवाही की पुरजोर निंदा की जानी चाहिए। भारत सरकार को, संयुक्त राष्ट्र संघ से वहां पर हस्तक्षेप करने की मांग करनी चाहिए। अंतराष्ट्रीय समुदाय का दल वहां जाए। चीन वहां जिस प्रकार की कार्यवाही कर रहा है, जिस प्रकार से वहां पर मानवता को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, नरसंहार हो रहा है, इसकी जांच

करके चीन के खिलाफ एक संयुक्त कार्यवाही करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I stand here to refer to the massacre of Buddhist monks in Tibet and continued oppression in Lhasa by Chinese authorities. I have two points to make relating to Tibet.

First, I condemn the use of brutal force by China on the peaceful demonstration of Buddhist monks which has led to killings of more than hundreds of people. The mass upsurge is not confined to Lhasa only; China's North-West Gansu Province near Tibet has also witnessed mass protest. Tibetans are protesting and are out on the streets to protect their cultural identity and to preserve their distinctiveness. What is happening today in Tibet and Gansu is that the Hans are imposing their culture on Tibet. For more than a decade, China has launched accelerating waves of campaign to force the Buddhist clergy to distance themselves from the Dalai Lama. Monks are ordered to renounce him while the common people are dissuaded not to pray to him. India should stand up against any type of ethnic cleansing in any part of the world. We should join international community not only to express our concern but should also tell China to exercise restraint and immediately stop its vitriolic attack on His Holiness, the Dalai Lama. Cultural genocide should stop.

Secondly, China is our neighbour and undoubtedly, it is in our national interest to maintain friendly relations with China. Our country has a tradition of permitting peaceful and non-violent protest against the ruling authorities in India and elsewhere. Criticism of some activities of Chinese Government in Tibet, particularly in Lhasa, cannot be termed as indulgence in political activities. The return march to Tibet, a non-violent peace march, is mainly intended to arouse the conscience of the international community to the plight of the Tibetan people. It is truly disturbing to witness the over-eagerness of this Government not to ruffle Chinese susceptibilities even after provocative Chinese statements regarding Arunachal Pradesh. I urge upon this Government not to disrespect the basic right of expression of protest in a peaceful, non-violent manner in our country. We should join the world community to denounce the use of brutal force by the Chinese Government on Tibetans. India should stand up and demand UN intervention in Tibet immediately.

सभापति महोदय : सभी मुद्दों को इसमें मत लाइए। अभी ह्युमन राइट्स पर चर्चा करेंगे।

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति महोदय, नेता सदन यहां बैठे हुए हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है, आप बैठिए।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, चीन की ओर से तिब्बत में जो मानव संहार हो रहा है, भिक्षुओं पर हमला हो रहा है, जिसमें 100 से भी ज्यादा भिक्षु लोग मारे गए हैं। मानवता का हनन करने का प्रयत्न चाइना की ओर से हो रहा है।[R20]

धार्मिक गुरु दलाई लामा जी ने स्वायत्तता की मांग की है, पूरी आजादी नहीं मांगी है। इसलिए उन्होंने जैसे ताइवान में रिपब्लिक आफ चाइना आन ताइवान है, उसी तरह से रिपब्लिक आफ चाइना आन तिब्बत को स्वायत्तता देने की बात कही है। भारत सरकार को इसमें मध्यस्थता करने की आवश्यकता है। अगर वक्त आ जाता है तो चाइना को चैलेंज देने की भी आवश्यकता है। इसलिए भारत सरकार को मध्यस्थता करनी चाहिए। धार्मिक गुरु दलाई लामा जी हमारे देश में 50 वर्षों से रह रहे हैं। इसलिए भारत की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है और भारत को चीन के साथ बात करनी चाहिए।

सभापति महोदय : इस विषय पर बहुत सारे सदस्यों ने अपना नाम दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि *m06 श्री सवाई, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, श्री विजय कृष्ण के नाम भी इस विषय के साथ जोड़े जाएं। अब हम दूसरा विषय लेते हैं और मैं श्री गुरुदास दासगुप्ता को मौका देता हूं।

...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : सदन के नेता बैठे हुए हैं, उन्हें इस पर जवाब देना चाहिए।

सभापति महोदय: सरकार को कम्पैल नहीं किया जा सकता। आपने अपनी बात कह दी, सरकार ने सुन लिया। सरकार को बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: गुरुदास दासगुप्ता जी की बात के अलावा और कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

* Not recorded

सभापति महोदय: आसन से सरकार को वक्तव्य देने का आदेश नहीं हो सकता। आपने अपनी बात कह दी, सरकार ने सुन ली। अब दूसरा विषय ले लिया गया है। इसलिए श्री

गुरुदास दासगुप्ता जी के अलावा और कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

सभापति महोदय: आप लोग बैठ जाएं, आपकी बात हो गई है।

SHRI THUPSTAN CHHEWANG (LADAKH): Sir, I want to associate with this matter.

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): विदेश मंत्री जी यहां बैठे हैं, वह अपना बयान पढ़कर सुनाएंगे।

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, I have listened to the observations made by the hon. Members on Tibet. Yesterday we have expressed our concern. So, it is not correct to say that we have not responded to the situation. I am quoting the statement which has been made. I quote:

> "We are distressed by reports of the unsettled situation and violence in Lhasa, and by the deaths of innocent people. We would hope that all those involved will work to improve the situation and remove the causes of such trouble in Tibet, which is an autonomous region of China, through dialogue and non-violent means."

सभापति महोदय: ठीक है, अब बात पूरी हो गई। विदेश मंत्री जी का वक्तव्य हो गया है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप इस बारे में नोटिस दें।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या यही बयान होता है?

सभापति महोदय: शून्य काल में इतना ही होता है। आप तो पुराने सदस्य हैं। शून्य काल के आप पारंगत व्यक्ति हैं।

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): सभापति जी, मुझे भी इस विषय पर बोलने का मौका दें।

---

* Not recorded

सभापति महोदय: मंत्री जी के वक्तव्य के बाद इस विषय पर कोई बात नहीं होगी। आपने नोटिस भी नहीं दिया है। अगर आपको बोलना है तो पहले उसके लिए नोटिस दें। मंत्री जी का वक्तव्य हो गया है। अगर आप इस पर चर्चा चाहते हैं तो नियम 193 के अंतर्गत नोटिस दें। वह कंसिडर किया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : हम मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : वहां पर इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, सरकार ने उसकी निंदा तक नहीं की। हम विदेश मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं और इसके विरोध में सदन से वाकआउट करते हैं।

12.49 hrs.

Prof. Vijay Kumar Malhotra and some other hon. Members then left the House.

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आपको प्रोटेस्ट करने का पूरा हक है। लेकिन पहले एनडीए के घटक दल बैठकर बयान तैयार कर लें कि किस प्रकार से इसकी निंदा की जाए। उसकी एक कापी हमें भेज दें।...(व्यवधान) [R21]

SHRI PRANAB MUKHERJEE : What did they do when they were in Government from 1998 to 2004? Shri Atal Bihari Vajpayee was the Minister of External Affairs from 1977 to 1979. So far as China and Tibet are concerned, the policy is being formulated from 1959, and all the incumbent Governments of India since then have not changed any policy in respect of China and Tibet.